भारत का सर्वोच्च न्यायालय

पश्चिम बंगाल राज्य

बनाम

मोतीलाल कनोरिया

15/03/1966

[पी. बी. गजेन्द्रगडकर, सी. जे., के. एन. वांचू, एम. हिदायतुल्ला, जे. सी. शाह और एस. एम. सिकरी, जे. जे.]

1947 का आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम 18, एस. 5-आयात (नियंत्रण) 1955 का आदेश क्रमांक 17, सीएल। (5)-अन्तर्गत आयातित वस्तुएँनियंत्रक की अनुमति के बिना बेचा गया लाइसेंस-ऐसी बिक्रीचाहे अपराध हो.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1898, एस. 537-त्रुटि, कमीशन शिकायत में अनियमितताओं की धारा का अनुप्रयोग.

प्रतिवादी एक कंपनी का निदेशक था और एक भी इसे प्रबंधित करने वाली फर्म में भागीदार। कंपनी की ओर से के तहत उन्होंने आयात लाइसेंस के लिए आवेदन किया आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम 1947, और मई 1955 में लाइसेंस प्रदान किया गया। उस समय लाइसेंस देना था। धारा 1948 के तहत जारी एक आदेश द्वारा शासित। 32 का अधिनियम,

और उस आदेश के तहत आयात नियंत्रक और निर्यात उसके द्वारा जारी किए गए लाइसेंस के लिए शर्तें जोड़ सकता है।को दिए गए लाइसेंस की शर्तों के अनुसार उपरोक्त कंपनी ने लाइसेंस के तहत सामान आयात किया था कंपनी के स्वयं के उपयोग के लिए नियोजित किया जाना है। दिसंबर 1955 में 1955 का आयात (नियंत्रण) आदेश संख्या 17 पारित किया गया। सीएल के तहत. आदेश के 5(3) में कुछ शर्तें मानी गईं प्रत्येक लाइसेंस का हिस्सा बनने के लिए और सीएल के तहत। 5(4) प्रत्येक की स्थिति का निरीक्षण करने का निर्देश लाइसेंसधारी को दिया गया लाइसेंस। 1956 में प्रतिवादी ने पुनर्वेधीकरण प्राप्त किया ।

कंपनी को जारी किया गया लाइसेंस. इसके बाद जब माल आ गया, उसे प्रतिवादी ने दूसरे को बेच दिया । प्रतिवादी और के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी के तहत अपराध के लिए कंपनी। आयात और निर्यात के 5 (नियंत्रण) अधिनियम 1947 सीएल के साथ पढ़ें। (5) आयात का(नियंत्रण) आदेश 1955। प्रतिवादी को मुकदमे का सामना करना पड़ा आरोप लगाया और बिना किसी कार्यवाही में भाग लिया आपत्ति. उन्हें ट्रायल मजिस्ट्रेट द्वारा दोषी ठहराया गया था लेकिन जिस समय हाई कोर्ट ने उन्हें इस आधार पर बरी कर दिया बिक्री का लेन-देन दिसंबर में दर्ज किया गया था 1956, लाइसेंस की शर्त का उल्लंघन एक अपराध नहीं बनताएस के तहत अपराध 1947 के अधिनियम के 5. राज्य ने अपील की इस न्यायालय को. वे प्रश्न जो निर्णय के लिए गिरे थे:

(i) क्या आयातित माल का निपटान करके बिना अनुमति के कोई अपराध किया गया; और

(ii) यदि हां क्या प्रतिवादी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी था।

आयोजित:

(i) यद्यपि एस. आयात और निर्यात के 5 (नियंत्रण) अधिनियम, 1947, 1960 में अपने संशोधन से पहले, नहीं था विशेष रूप से लाइसेंस की शर्त का उल्लंघन प्रदान करें आयात (नियंत्रण) का उल्लंघन माना जाएगा आदेश, फिर भी सीएलएस के आधार पर। 5(3) और (4) सीएल के साथ पढ़ें। 12 आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 का स्थानांतरणलाइसेंस उक्त आदेश का उल्लंघन था और गठित किया गया

अपराध। में वैध रूप से कोई भेद नहीं किया जा सका लाइसेंस के हस्तांतरण और के बीच इस मामले की परिस्थितियाँ इसके अंतर्गत आयातित माल का स्थानांतरण। [945 ईजी; 946 ईसा पूर्व]

सीटीएस पिल्लई बनाम एचपी लोहिया और अन्य। एआईआर 1957 कैल. 83, करने के लिए भेजा।

ईस्ट इंडिया कमर्शियल कंपनी लिमिटेड कलकत्ता बनाम कलेक्टर ऑफ

सीमा शुल्क, कलकत्ता, [1963] 3 एससीआर 338

स्टेट बनाम अब्दुल अजीज [1964] 1 एससीआर 830, लागू।(ii) तथ्य यह है कि लाइसेंस 'द' द्वारा प्राप्त किया गया थाप्रतिवादी ने, जबकि 1948 का आदेश लागू था, ऐसा नहीं किया सीएल के तहत प्रतिवादी की मदद करें। 1955 के 12 आदेश कोई भी पहले के किसी भी आदेश के तहत जारी किया गया लाइसेंस माना जाएगा के संगत प्रावधानों के तहत जारी किये गये हैं 1955 आदेश. इसके अलावा, लाइसेंस के तहत सामान थे, 1955 के बाद आयातित और बेचा गया। लाइसेंस ही था 1956 में पुनः वैधीकरण किया गया और यह केवल द्वारा ही किया जा सकता थासीएल के अंतर्गत प्राप्त शक्ति। 1955 के आदेश के 7. [945 बी, डी]

(iii) प्रतिवादी जारी करने के लिए जिम्मेदार था लाइसेंस और के तहत आयातित माल के हस्तांतरण के लिए

यह। इसलिए वह मुख्य रूप से इसके लिए जिम्मेदार था कंपनी। नि:संदेह यह स्पष्ट नहीं है कि शिकायत किसकी है वास्तव में मुकदमा चलाने का इरादा था लेकिन इसने इसका वर्णन किया प्रतिवादी को एक अभियुक्त के रूप में जिस पर उसने कोई आपत्ति नहीं जताई परीक्षण। में त्रुटि, चूक या अनियमितता, यदि कोई होएस के तहत शिकायत का इलाज संभव था । आपराधिक संहिता की धारा 537 प्रक्रिया और वर्तमान मामले में ऐसा नहीं कहा जा सकता है न्याय की विफलता का कारण बना। [946 ईएच]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 108/1964।

1962 के आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 396 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के 4 सितंबर, 1963 के फैसले और आदेश के खिलाफ अपील।

अपीलकर्ता की ओर से देब्रत मुखर्जी, बीएल मेहता, आरएच ढेबर और बीआरजीके अचार।

प्रतिवादी की ओर से डीएन मुखर्जी।

अदालत का फैसला हिदायतुल्ला, जे. द्वारा सुनाया गया। यह कला के तहत प्रमाण पत्र द्वारा एक अपील है। संविधान की धारा 134 (1) (सी), 4 सितंबर 1963 के कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ, जिसके द्वारा प्रतिवादी मोतीलाल कनोरिया को धारा के तहत दोषी ठहराया गया था। आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 की धारा 5 और रुपये के जुर्माने की सजा। प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट, 6 वीं अदालत, कलकत्ता द्वारा लगाए गए 200/(डिफ़ॉल्ट रूप से एक महीने के लिए साधारण कारावास) को रद्द कर दिया गया और बरी कर दिया गया। मामले के तथ्य विवाद में नहीं हैं और इसलिए उन्हें संक्षेप में बताया जा सकता है। मोतीलाल कनोरिया लछमीनारायण जूट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता के निदेशक थे। कंपनी का प्रबंधन मुखराम लछमीनारायण नाम की एक फर्म द्वारा

किया जाता था और मोतीलाल कनोरिया फर्म के भागीदारों में से एक थे। कंपनी और प्रबंध एजेंटों का कलकत्ता में एक ही पता था। मोतीलाल कनोरिया प्रबंध एजेंटों की ओर से हस्ताक्षर करते थे और आम तौर पर कंपनी के मामलों से भी निपटते थे। इस मामले में सभी लेनदेन मोतीलाल कनोरिया द्वारा किए गए थे और उन्होंने उन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे जिनका संदर्भ वर्तमान में किया जाएगा।

फरवरी 1955 में भारत सरकार ने हैकल और कॉम्बिंग पिन बनाने के कंपनी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और 935 उद्देश्य के लिए संयंत्र और मशीनरी के आयात को मंजूरी दे दी। कंपनी को लाइसेंस के लिए मुख्य आयात नियंत्रक, नई दिल्ली को आवेदन करने की अनुमति दी गई थी। शासन का पत्र पूर्व है। 2 दिनांक 4 फ़रवरी 1955. द्वितीय फ़रवरी को. 1955 कंपनी ने आयात लाइसेंस के लिए उचित आवेदन पत्र पर मुख्य आयात नियंत्रक, नई दिल्ली को आवेदन किया। उस आवेदन में कंपनी ने कहा था कि मशीनरी कोन्नग्गर, पूर्वी रेलवे (उदा. 1) में उनकी मिलों में स्थापित या उपयोग की जानी थी। 26 मई, 1955 को एक लाइसेंस जारी किया गया (उदाहरण 3)। लाइसेंस इस प्रकार पढ़ा गया--

> "यह लाइसेंस वर्तमान लाइसेंसिंग अवधि के लिए पॉलिसी बुक में वर्णित लाइसेंस प्राप्त माल की शर्तों और समय-समय पर इस संबंध में जारी किए जाने वाले किसी

भी सार्वजनिक नोटिस के अधीन जारी किया जाता है। लाइसेंस संख्या 035925 काउंटरफॉइल विदेशी मुद्रा के लिए उपलब्ध नहीं है जब तक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिकृत न किया जाए। आयात व्यापार नियंत्रण (सभी भारतीय बंदरगाहों के लिए मान्य) (लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकारी या किसी आयात व्यापार नियंत्रक से प्राधिकार पत्र के अलावा हस्तांतरणीय नहीं)। मेसर्स श्री लुचमिनारेन जूट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। लिमिटेड, 59, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता-

1. एतद्द्वारा उन वस्तुओं को आयात करने के लिए अधिकृत हैं जिनका विवरण नीचे दिया गया है:-

1. वह देश जहाँ से भेजा गया: पश्चिमी जर्मनी।

2. सामान के अनुसार मात्रा और विवरण मशीनरी: हैकलिंग और कॉम्बिंग पिन के निर्माण के लिए सूची संलग्न है।

3. अनुमानित मूल्य सीआईएफ रु. 1,88,000/- (एक लाख अट्ठासी हजार रूपये मात्र)

4. शिपमेंट की अवधि: 31 मई 1957 तक पुनः वैध।

5. मैसर्स का नाम और पता। शूनाकर मेटल निर्माता शिपर या वर्क्स अक्तीएंगेस्चे आपूर्तिकर्ता: इलाचेफ्ट, आचेन, जर्मनी।

6. सीमा शुल्क के माध्यम से समाशोधन के प्रयोजन के लिए सीमित कारक: मूल्य

7. सेल्फ इंडिया में वास्तविक उपयोगकर्ता का नाम यह लाइसेंस भारत सरकार, देर से वाणिज्य विभाग अधिसूचना संख्या 23 के तहत प्रदान किया जाता है। आईटीसी/43 दिनांक 1 जुलाई 1943 जैसा कि आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम 1947 18 द्वारा लागू है। 1947) और उसके तहत जारी नियमों और आदेशों के अधीन। यह लाइसेंस माल के आयात को प्रभावित करने वाले किसी भी अन्य निषेध या विनियम के अनुप्रयोग पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है जो उनके आगमन के समय लागू हो सकता है।

एस.डी. आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक के लिए अपठनीय अनुभाग अधिकारी 26-5-55। 26-5-1955.

फाइल क्रमांक एल. IV/49(11) CG/55 से जारी। (आयात व्यापार नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदन के

लिए स्थान) यह लाइसेंस जारी होने की तारीख से एक वर्ष की प्रारंभिक वैधता अवधि के साथ जारी किया जाता है। इसे एक वर्ष की उक्त अवधि के अंत में या उससे पहले, दो वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए पुनः मान्य किया जाएगा, बशर्ते कि संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत किया जाए कि माल का ऑर्डर विदेशी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और एक पक्का अनुबंध किया गया है। एक वर्ष की प्रारंभिक अवधि. हालाँकि, किसी भी स्थिति में, वैधता अवधि जारी होने की तारीख से तीन साल से अधिक नहीं बढ़ेगी।"

कवरिंग लेटर में, जो लाइसेंस अग्रेषित करते समय भेजा गया था, मुख्य नियंत्रक ने अन्य बातों के साथ-साथ कहा, -

(3). आपको निम्नलिखित शर्तों के अधीन लाइसेंस प्रदान किया जाता है:-

(ए) यदि परियोजना में कोई पूंजीगत मुद्दा शामिल है और यदि ऐसे पूंजीगत मुद्दे को मंजूरी नहीं दी गई है तो लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।

(बी) कि यदि केंद्रीय, प्रांतीय कानूनों के तहत परियोजना के लिए कोई मंजूरी आवश्यक है-

इसे प्राप्त किया जाना चाहिए और स्थिति की सूचना लाइसेंसधारी द्वारा इस कार्यालय को दी जानी चाहिए; ऐसी मंजूरी प्राप्त न होने पर लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।

4. यदि संलग्न पर्ची में दिए गए विस्तृत निर्देशों के अनुसार समय की प्रगति के बारे में विवरण नहीं दिया गया तो लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।

5. सरकार वस्तुओं के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल की आपूर्ति की गारंटी नहीं देती है।

19 जून, 1956 को कंपनी ने लाइसेंस के "पुनर्वेधीकरण" के लिए कहा और लाइसेंस को 31 मई, 1957 तक बढ़ा दिया गया। इस विस्तार का उल्लेख ऊपर दिए गए लाइसेंस में नंबर 4 पर किया गया है। 13 दिसंबर, 1956 को कंपनी ने एक समझौता किया। कंपनी द्वारा आयातित मशीनरी की बिक्री के लिए कलकत्ता के शालीमार वुड प्रोडक्ट्स (पी) लिमिटेड के साथ समझौता (उदा. 25)। यह प्रस्तुत किया गया है कि बिक्री चालान मूल्य पर थी और कोई लाभ नहीं हुआ। अगले वर्ष फरवरी में मशीनरी के आगमन पर कंपनी ने शालीमार वुड प्रोडक्ट्स को कंपनी के बैंकरों से शिपिंग दस्तावेज़ प्राप्त करने और डॉक्स से इसे साफ़ करने के लिए अधिकृत किया। प्लांट और मशीनरी को शालीमार वुड प्रोडक्ट्स के एजेंटों द्वारा मंजूरी दे दी गई और बाद वाले ने उन्हें अपने कारखाने में स्थापित

करने के उद्देश्य से ले लिया। 30 जुलाई, 1958 को कंपनी ने मुख्य आयात नियंत्रक को एक पत्र (उदा. 7) लिखकर सूचित किया कि उनके निदेशक सावल राम कनोरिया की मृत्यु के कारण, जो उक्त पिन के उत्पादन में रुचि रखते थे, कंपनी को मजबूर होना पड़ा। आयातित संयंत्र और मशीनरी को शालीमार वुड प्रोडक्ट्स को बेचें। (पी) लिमिटेड, कलकत्ता और लेनदेन की मंजूरी के लिए कहा। आयात के मुख्य नियंत्रक ने जवाब में बताया कि हस्तांतरण से पहले अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए थी और कंपनी ने स्पष्ट रूप से आयात लाइसेंस का उल्लंघन किया है। जांच के लिए पुलिस को एक रिपोर्ट दी गई और बाद में आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 की धारा 5 के तहत आयात और निर्यात के उप मुख्य नियंत्रक द्वारा मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट, कलकत्ता की अदालत में एक शिकायत दायर की गई। लछमीनारायन जूट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को "श्री मोतीलाल किनोरिया द्वारा प्रतिनिधित्व" आरोपी के रूप में नामित किया गया था। शिकायत के पैराग्राफ 2 में कंपनी को आरोपी बताया गया था लेकिन शिकायत के बाद के पैराग्राफ में मोतीलाल कनोरिया को आरोपी के रूप में नामित किया गया था। प्रार्थना में अनुरोध किया गया था कि अदालत को पीसीआई/66-14 के उल्लंघन के आरोप का जवाब देने के लिए "कंपनी और प्रबंध एजेंटों का प्रतिनिधित्व करने वाले आरोपी मोतीलाल कनोरिया" को बुलाना चाहिए। लाइसेंस की शर्तें जो धारा के तहत अपराध बनती हैं। आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के 5, 1955 के आयात (नियंत्रण)

आदेश संख्या 17, दिनांक 17 दिसंबर, 1955 के खंड (5) के साथ पठित। मोतीलाल कनोरिया मुकदमे में उपस्थित हुए, उनसे एक आरोपी के रूप में पूछताछ की गई, दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और मुकदमा चलाया। ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि उन्होंने एक आरोपी व्यक्ति के रूप में दोषी ठहराए जाने पर आपत्ति जताई है, जैसा कि उन्होंने बाद में उच्च न्यायालय में उठाया था और हमारे सामने भी रखा है। अभियोजन पक्ष ने उपरोक्त तथ्यों को साबित करने के लिए बड़ी संख्या में गवाहों की जांच की और दस्तावेज दाखिल किए, जिनमें से किसी को भी अब अस्वीकार नहीं किया गया है। प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट, छठी अदालत, कलकत्ता ने कनोरिया को धारा के तहत दोषी ठहराया। आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 के खंड (5) के उल्लंघन के लिए आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 की धारा 5 और रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। 200/- अथवा एक माह का साधारण कारावास। पुनरीक्षण पर उच्च न्यायालय ने उन्हें बरी कर दिया लेकिन मामले को इस न्यायालय में अपील के लिए उपयुक्त प्रमाणित किया और वर्तमान अपील इसका परिणाम है। जैसा कि अभियोजन धारा के तहत एक अपराध के संबंध में है। आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के 5 में, हम यह जांच कर शुरू करेंगे कि उस अपराध के तत्व क्या हैं। उस अधिनियम की योजना के तहत आयात को प्रतिबंधित या प्रतिबंधित करने की शक्ति है । 3 केंद्र सरकार उन्हें प्रतिबंधित करने, प्रतिबंधित करने या अन्यथा नियंत्रित करने के लिए, आधिकारिक राजपत्र

में प्रकाशित आदेश द्वारा प्रावधान करने में सक्षम है। धारा 5 किसी आदेश के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान करती है। अधिनियम 4 1960 द्वारा संशोधित धारा यहां दी गई है

> "5. यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के तहत किए गए किसी भी आदेश या लाइसेंस की किसी शर्त का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयास करता है, या उल्लंघन के लिए उकसाता है ऐसे किसी भी आदेश के तहत दिए जाने पर, वह किसी भी जब्ती या जुर्माने पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जिसके लिए वह समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम, 1878 के प्रावधानों के तहत उत्तरदायी हो सकता है, जैसा कि धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा लागू किया गया है, कारावास से दंडनीय होगा । एक अवधि के लिए जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जा सकता है"।
>
> (रेखांकित शब्द 1960 में प्रस्तुत किये गये थे)।

इस संशोधन के बाद इस मामले में शिकायत दर्ज की गई थी. धारा 3 के तहत केंद्र सरकार द्वारा अलग-अलग समय पर अलग-अलग आदेश पारित किए गए और 1943 और 1948 के आदेशों के बारे में एक शब्द भी

कहा जा सकता है, हालांकि मशीनरी के हस्तांतरण की तारीख (13 दिसंबर, 1956) पर केवल 1955 का आदेश था लागू।

पहला आदेश 1943 में लागू भारत रक्षा नियमों के नियम 84 के उप-नियम (3) के तहत दिया गया था (अधिसूचना संख्या 23 आईटीसी/ 43 दिनांक 1 जुलाई, 1943)। वह आदेश सामान्य था और लाइसेंस में शर्तों को लागू करने का अधिकार देने वाला कोई प्रावधान नहीं था, जिसका उल्लंघन आदेश का उल्लंघन माना जाएगा।

1948 में एस के तहत एक और आदेश जारी किया गया। 3 (अधिसूचना संख्या 2 आईटीसी दिनांक 6 मार्च 1948)। इसमें शर्तों को लागू करने का प्रावधान था लेकिन आदेश के प्रावधानों ने यह संकेत नहीं दिया कि किसी विशेष शर्त को लाइसेंस में शामिल माना जाएगा यदि स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है। उस आदेश के प्रावधान यहां पढ़े जा सकते हैं:

> "आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार निम्नलिखित बनाने में प्रसन्न है आदेश अर्थात्:-
>
> (ए) भारत सरकार के वाणिज्य विभाग संख्या 23 आईटीसी/43, दिनांक 1 जुलाई, 1943 की अधिसूचना के

खंड (viii) से (xiv) के तहत लाइसेंस जारी करने वाला कोई भी अधिकारी, उसी विषय को जारी कर सकता है। नीचे दी गई शर्तों में से एक या अधिक के लिए:

(i) कि लाइसेंस के अंतर्गत आने वाले सामान का निपटान या अन्यथा निपटान लाइसेंसिंग प्राधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति की लिखित अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा;

(ii) आयात पर लाइसेंस के अंतर्गत आने वाले सामान को लाइसेंस से जुड़े किसी भी निर्देश में निर्दिष्ट कीमत से अधिक कीमत पर बेचा या वितरित नहीं किया जाएगा;

(iii) कि लाइसेंस के लिए आवेदक उन शर्तों के अनुपालन के लिए एक बांड निष्पादित करेगा जिसके अधीन लाइसेंस दिया जा सकता है;

(iv) लाइसेंस प्राधिकारी या उसके द्वारा विधिवत अधिकृत व्यक्ति की अनुमति के बिना लाइसेंस हस्तांतरणीय नहीं होगा;

(v) ऐसी अन्य शर्तें लगाई जा सकती हैं जिन्हें लाइसेंसिंग प्राधिकारी प्रशासनिक दृष्टिकोण से समीचीन

मानता है और जो उक्त अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हैं।

(बी) जहां किसी लाइसेंस में आदेश या लाइसेंस में शामिल नियमों और शर्तों का उल्लंघन पाया जाता है, तो उपयुक्त लाइसेंसिंग प्राधिकारी या आयात के मुख्य नियंत्रक उसे सूचित कर सकते हैं, बिना किसी दंड के पूर्वाग्रह के। आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18), या उस समय लागू किसी अन्य अधिनियम के तहत उत्तरदायी हो सकता है, उसे या तो स्थायी रूप से या एक निर्दिष्ट अवधि के लिए माल के आयात के लिए किसी भी अन्य लाइसेंस से इनकार कर दिया जाएगा।

इस आदेश के द्वारा लाइसेंसिंग प्राधिकारी को लाइसेंस में शर्तें शामिल करने की शक्ति दी गई।

7 दिसम्बर, 1955 को एक आदेश जारी किया गया (अधिसूचना संख्या 17/55 दिनांक 7 दिसम्बर, 1955)। इसने सभी नियमों को एक ही स्थान पर समेकित किया और अनुसूची IV के साथ पढ़े गए खंड 12 द्वारा पहले के दो आदेशों और कुछ अन्य को निरस्त कर दिया, लेकिन इस निरसन को प्रभावी करते हुए इसमें एक बचत खंड जोड़ा गया--

"बशर्ते कि उपरोक्त आदेशों में से किसी के तहत की गई नियुक्ति या जारी किए गए लाइसेंस सहित कुछ भी किया गया या की गई कोई कार्रवाई, इस आदेश के संबंधित प्रावधान के तहत की गई या की गई मानी जाएगी।"

1955 के आदेश में शर्तों के संबंध में कई नए प्रावधान भी शामिल थे जिन्हें लाइसेंस और अन्य में पेश किया जा सकता था जिन्हें इस तरह पेश किया गया माना जाएगा। यहां प्रासंगिक शर्तों पर ध्यान दिया जा सकता है।

"5. लाइसेंस की शर्तें.

(1) इस आदेश के तहत लाइसेंस जारी करने वाला लाइसेंस प्राधिकारी नीचे बताई गई एक या अधिक शर्तों के अधीन इसे जारी कर सकता है: -

(i) कि लाइसेंस के अंतर्गत आने वाले सामान का निपटान, लाइसेंसिंग प्राधिकारी या उसके द्वारा विधिवत अधिकृत किसी व्यक्ति की लिखित अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा, या अन्यथा निपटारा नहीं किया जाएगा;

(ii) आयात पर लाइसेंस के अंतर्गत आने वाले सामान को लाइसेंस से जुड़े किसी भी निर्देश में निर्दिष्ट मूल्य से अधिक कीमत पर बेचा या वितरित नहीं किया जाएगा;

(iii) कि लाइसेंस के लिए आवेदक उन शर्तों का अनुपालन करने के लिए एक बांड निष्पादित करेगा जिसके अधीन लाइसेंस दिया जा सकता है।

(3) यह ऐसे प्रत्येक लाइसेंस की एक शर्त मानी जाएगी कि:

(i) कोई भी व्यक्ति लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए किसी भी लाइसेंस को हस्तांतरित नहीं करेगा और न ही हस्तांतरण द्वारा प्राप्त करेगा, सिवाय उस प्राधिकारी की लिखित अनुमति के तहत जिसने लाइसेंस दिया है या ऐसे प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में सशक्त किसी अन्य व्यक्ति की अनुमति दी गई है।

(ii) जिस सामान के आयात के लिए लाइसेंस दिया गया है वह आयात के समय और उसके बाद सीमा शुल्क के माध्यम से निकासी के समय तक लाइसेंसधारी की संपत्ति होगी।

(iii) जिस सामान के आयात के लिए लाइसेंस दिया गया है वह नया सामान होगा जब तक कि लाइसेंस में अन्यथा न कहा गया हो।

(4) लाइसेंसधारी इस खंड के तहत लगाई गई या लगाई गई समझी जाने वाली सभी शर्तों का पालन करेगा।"

शर्तें 5 (1) (i), (ii) और (iii) और 5 (3) (i) 1948 के आदेश की शर्तों (ए) (i) से (iv) के समान हैं लेकिन 5 (3) (ii)) और (iii) और 5 (4) नए हैं। शर्तें 5 (3) (i),

(ii) और (iii) प्रत्येक लाइसेंस का हिस्सा बन जाते हैं और इसके अलावा लाइसेंसधारी को खंड 5 के तहत लगाई गई या लगाई गई समझी जाने वाली सभी शर्तों का पालन करना होगा। इन खंडों के प्रभाव को दिए गए लाइसेंस के संबंध में विचार किया जाना चाहिए यह मामला लेकिन इस संदर्भ में खंड 7 के प्रावधान भी प्रासंगिक हैं और खंड यहां निर्धारित किया जा सकता है:

"7. लाइसेंस का संशोधन.--

लाइसेंसिंग प्राधिकारी, अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या लाइसेंसधारी द्वारा आवेदन पर, इस आदेश के तहत दिए गए किसी भी लाइसेंस में इस तरह से संशोधन कर सकता है, जो ऐसे लाइसेंस को अधिनियम या इस आदेश या किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अनुरूप बनाने के लिए आवश्यक हो सकता है। समय से लागू होने या लाइसेंस में किसी भी त्रुटि या चूक को सुधारने के लिए; बशर्ते कि

लाइसेंसिंग प्राधिकारी, लाइसेंसधारक के अनुरोध पर, आयात व्यापार नियंत्रण विनियमों के अनुरूप किसी भी तरीके से लाइसेंस में संशोधन कर सकता है।"

इस मामले में अधिकांश तर्क इन अधिसूचनाओं की तारीखों और अधिनियम की धारा 5 के संशोधन पर आधारित हैं, जिन तारीखों के संबंध में इस मामले में कई तथ्य सामने आए हैं। प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट ने 1955 के आदेश को लागू किया क्योंकि लाइसेंस 27 जून, 1956 को "पुनर्वैध" कर दिया गया था, और उनके अनुसार, यह स्पष्ट रूप से उस आदेश के खंड 7 से प्राप्त शक्तियों के तहत किया गया था। प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट के अनुसार कंपनी ने अपने उपयोग के लिए संयंत्र और मशीनरी का आयात किया था (लाइसेंस की संख्या 7 के अनुसार) और यह लाइसेंस की एक स्पष्ट शर्त थी। उन्होंने यह भी बताया कि लाइसेंस को स्पष्ट रूप से ऐसे प्रतिबंधों के अधीन बनाया गया था जो समय-समय पर लगाए जा सकते हैं और 1955 के आदेश ने ऐसी शर्तें लगाईं जिससे मशीनरी के हस्तांतरण को अपराध बना दिया गया जो कि उपधारा (3) खंड (5) का उल्लंघन है। 1955 का आदेश. उच्च न्यायालय ने माना कि एस. अधिनियम की धारा 5, जैसा कि 13 दिसंबर, 1956 को लागू थी जब कथित अपराध किया गया था, लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन को अपराध नहीं बनाता था और इसलिए, कोई अपराध नहीं था । डिवीजन बेंच ने मुख्य रूप से सेन और मित्तर जेजे की

टिप्पणियों पर भरोसा किया। सीटीएस पिल्लई बनाम एचपी लोहिया और अन्य (1) में निम्नलिखित प्रभाव:

> "इसलिए, यह स्पष्ट है कि धारा केवल अधिनियम के तहत किए गए या किए गए किसी भी आदेश के उल्लंघन को दंडित करती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अधिनियम के तहत जारी किए गए लाइसेंस द्वारा लगाई गई शर्त का उल्लंघन है या वैधानिक आदेश के तहत जारी किया गया है अधिनियम के तहत बनाया गया आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 की धारा 5 के तहत भी एक अपराध है। हालांकि लाइसेंस अधिनियम के तहत बनाए गए वैधानिक आदेश के तहत दिया जाता है और अधिनियम के तहत बनाए गए किसी अन्य वैधानिक आदेश के तहत लाइसेंस में शर्तें लगाई जा सकती हैं । यह मानना मुश्किल है कि लाइसेंस या लाइसेंस की शर्तें अधिनियम के तहत किए गए आदेश या किए गए माने जाते हैं। अधिसूचना संख्या 23। आईटीसी/43 दिनांक 1-7-1943 केवल यह प्रदान करता है कि कोई भी सामान नहीं बेचा जाएगा एक अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किए गए विशेष लाइसेंस द्वारा कवर किए गए सामान को छोड़कर आयात किया गया। अधिसूचना संख्या 2-आईटीसी/48 दिनांक 6-3-1948 एक

लाइसेंसिंग अधिकारी को उस आदेश में निर्धारित एक या अधिक शर्तों को लागू करने के लिए अधिकृत करता है और एक लाइसेंसिंग अधिकारी, इसलिए एक लगा सकता है अधिसूचना संख्या 2-आईटीसी/48 के प्रावधान के मद्देनजर स्थिति। लेकिन यदि लाइसेंसधारी लाइसेंस द्वारा लगाई गई शर्तों का उल्लंघन करता है तो यह मुश्किल से कहा जा सकता है कि उसने इस अधिनियम, यानी अधिसूचना संख्या 2-आईटीसी/48 के तहत आदेश का उल्लंघन किया है। आदेश संख्या 2-आईटीसी/48 सीधे तौर पर कोई शुल्क नहीं लगाता है लेकिन यह लाइसेंसिंग अधिकारी को कुछ शर्तें लगाने की शक्ति देता है। लेकिन शर्त का उल्लंघन - (1) एआईआर 1957 कैल। 83.

लाइसेंसिंग अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को प्रथम दृष्टया अधिसूचित आदेश का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है... जब कुछ वस्तुओं को कवर करने वाला एक विशेष लाइसेंस होता है और विशेष लाइसेंस में एक शर्त लगाई जाती है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि शर्त का उल्लंघन है विशेष लाइसेंस में लगाए गए यह नहीं कहा जा सकता है कि शर्त के उल्लंघन से आदेश 231 आईटीसी/43 या बाद की अधिसूचना संख्या 2-आईटीसी/48 का कोई उल्लंघन हुआ

है। यह उल्लेख किया जा सकता है कि कठिनाई स्पष्ट रूप से महसूस की गई थी पाकिस्तान और इसलिए आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947, को पहले एक अध्यादेश द्वारा और फिर पाकिस्तान के आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1950 द्वारा संशोधित किया गया था। उस अधिनियम की धारा 3(2) में प्रावधान है कि 'निर्दिष्ट विवरण का कोई भी सामान मुख्य नियंत्रक या केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जारी किए जाने वाले लाइसेंस की शर्तों के अनुसार आयात या निर्यात नहीं किया जाएगा। . दंडात्मक धारा 5 , न केवल अधिनियम के तहत बनाए गए किसी आदेश या नियम के उल्लंघन को संदर्भित करती है, बल्कि लाइसेंस द्वारा लगाई गई किसी भी शर्त के उल्लंघन को भी संदर्भित करती है... यह स्पष्ट है कि जब तक दंडात्मक धारा में स्वयं शामिल नहीं होता है लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन एक अपराध है, यह मानना संभव नहीं है कि लाइसेंसधारियों ने लाइसेंस द्वारा लगाई गई शर्तों का उल्लंघन करके ऐसा अपराध किया है जिसमें इसके तहत किए गए या किए गए समझे गए आदेश का उल्लंघन शामिल है। कार्यवाही करना। इस दृष्टि से, इसलिए, यद्यपि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए

कारणों को हमारे द्वारा उचित नहीं माना गया है, यह स्पष्ट है कि धारा के तहत विपरीत पक्ष पर मुकदमा चलाया जा रहा है। आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 का 5 विफल होना चाहिए।"

इन टिप्पणियों को ईस्ट इंडिया कमर्शियल कंपनी लिमिटेड, काकुट्टा बनाम सीमा शुल्क कलेक्टर, काकुट्टा (1) में इस न्यायालय के बहुमत के फैसले द्वारा संदर्भित किया गया था। उसके बाद के शब्द:-

कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के समक्ष, जिसमें मित्तर और सेन जे. अधिनियम के तहत किया जायेगा। विद्वान न्यायाधीशों ने एस का अर्थ लगाया। अधिनियम के 5 और माना गया कि उक्त धारा केवल उक्त अधिनियम के तहत किए गए या किए गए समझे गए आदेश के उल्लंघन को दंडित करती है, लेकिन दंडित नहीं करती (1) [1963] 3 एससीआर 338 एट 356, 369, 372।

अधिनियम के तहत जारी किए गए लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन या उस अधिनियम के तहत किए गए वैधानिक आदेश के तहत जारी किया गया, और संशोधन को खारिज कर दिया गया।

इस आदेश से यह स्पष्ट होगा कि इसमें लाइसेंस में यह शर्त नहीं दी गई है कि 'आयात के बाद माल बेचा नहीं जाना चाहिए।' सीएल की स्थिति

(v) (ए) केवल लाइसेंसिंग प्राधिकारी को प्रशासनिक दृष्टिकोण से एक शर्त लगाने का अधिकार देता है। यह नहीं कहा जा सकता कि जिस शर्त को लेकर हम अब चिंतित हैं, वह प्रशासनिक दृष्टिकोण से लगाई गई शर्त है, लेकिन यह एक शर्त है। जो पार्टियों के अधिकारों को प्रभावित करता है.

उपरोक्त से यह निष्कर्ष निकलता है कि लाइसेंस में तीसरे पक्ष को आयातित माल न बेचने की शर्त का उल्लंघन आदेश का उल्लंघन नहीं है.....

डिवीजन बेंच ने माना कि पहले के कलकत्ता मामले को मंजूरी दे दी गई थी। उपरोक्त टिप्पणियों के बाद विद्वान न्यायाधीशों ने उन्हें इस मामले में लागू किया। उन्होंने नोट किया कि किसी शर्त का उल्लंघन 17 मार्च 1960 के बाद ही अपराध बन गया जब 1960 का अधिनियम 4 पारित किया गया था और चूंकि यह पहले अपराध नहीं हो सकता था, भले ही 1955 के आदेश ने कुछ शर्तों को इसका हिस्सा माना हो। लाइसेंस, उनका उल्लंघन कोई अपराध नहीं था। उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट इल स्टेट बनाम अब्दुल अजीज (1) के फैसले को इस आधार पर अलग कर दिया कि उस मामले में लाइसेंस 2 जनवरी, 1956 को दिया गया था, यानी आदेश के लागू होने के बाद। 1955. इसलिए डिवीजन बेंच ने माना कि कोई अपराध नहीं किया गया था। इस तथ्य की ओर भी ध्यान दिलाते हुए कि इस बात को लेकर भ्रम था कि कंपनी या मोतीलाल कनोरिया दोनों में से कौन

आरोपी था, विद्वान न्यायाधीशों ने माना कि प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट ने कनोरिया को दोषी ठहराने में और भी गलती की, हालांकि अभियोजन वास्तव में कंपनी के खिलाफ था।

इस मामले में जो प्रश्न उठते हैं वे वास्तव में दो हैं और वे हैं:

(ए) क्या बिना अनुमति के संयंत्र और मशीनरी का निपटान करके कोई अपराध किया गया था; और (1) एएलआर 1962 बम। 24.

(ख) यदि हां, तो किसके द्वारा?

हमारे निर्णय में इन दोनों प्रश्नों का उत्तर पश्चिम बंगाल राज्य के पक्ष में दिया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय में इस बात की अनदेखी की गई कि 1955 के आदेश के खंड 12 के प्रावधान के तहत लाइसेंस, हालांकि उस आदेश के लागू होने से पहले दिया गया था, उसकी शर्तों के तहत आता था। उस प्रावधान के शब्द पहले के किसी भी आदेश के तहत जारी किए गए 'लाइसेंस' को संदर्भित करते हैं, जो कि 1955 के आदेश के संबंधित प्रावधान के तहत किया गया कुछ या कार्रवाई है। संबंधित शर्तें वे थीं जिन्हें हमने 1955 के आदेश से निकाला था और पहले निर्धारित किया था। लाइसेंस की शर्तों (आइटम नंबर 7) के अनुसार लाइसेंसधारी ने माल का उपयोग स्वयं करने का वचन दिया। उन्होंने खुद को

"माल के आयात को प्रभावित करने वाले किसी भी अन्य

निषेध या नियमों से बाध्य किया जो उनके आगमन के

समय लागू हो सकते हैं" और लाइसेंस को स्थानांतरित नहीं करने के लिए "उस प्राधिकारी से प्राधिकार पत्र के अलावा जिसने लाइसेंस जारी किया था या किसी भी आयात व्यापार नियंत्रक से"।

1955 का आदेश लागू होने के काफी समय बाद माल आया। खंड 7 के तहत पुनर्वैधीकरण की कार्रवाई और लाइसेंस की शर्तें, जैसी भी थीं, 1955 के आदेश के प्रावधानों को आकर्षित करती थीं। चूंकि खंड 5(3) और (4) लाइसेंस का हिस्सा बन गए, उनका उल्लंघन आदेश का उल्लंघन था और इसलिए, एक अपराध किया गया था। अब्दुल अजीज बनाम महाराष्ट्र राज्य (1) (बॉम्बे उच्च न्यायालय के उप.नाम राज्य बनाम अब्दुल अजीज मामले की अपील पर) में यह निर्णय लिया गया था कि यदि लाइसेंस 1955 के आदेश के तहत जारी किया गया था, तो इसके प्रावधान उप-सीएल. (4) सीएल का. 5 ने लाइसेंसधारी के लिए खंड 5 के तहत लगाई गई या लगाई गई समझी जाने वाली सभी शर्तों का अनुपालन करना अनिवार्य बना दिया और लाइसेंस की किसी भी शर्त का उल्लंघन उप-सीएल के प्रावधान के उल्लंघन के बराबर है। (4) सीएल का. आदेश के 5 और परिणामस्वरूप आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के तहत किए गए आदेश का उल्लंघन और इसलिए लाइसेंसधारी धारा के तहत दंड के लिए उत्तरदायी हो गया । 5 अधिनियम का. अब्दुल अज़ीज़ के मामले और इस मामले के बीच एकमात्र अंतर इस तथ्य में निहित है कि पूर्व में

लाइसेंस 1955 के आदेश के लागू होने के बाद और इस मामले में पहले दिया गया था। लेकिन यह अंतर तब महत्व खो देता है जब धारा 12 के प्रावधान 1955 के आदेश को लाइसेंस के साथ ही पढ़ा जाता है। उनके बीच वे 1955 के आदेश के खंड 5 को अमल में लाते हैं और अब्दुल अजीज के मामले में इस न्यायालय द्वारा पहुंचा गया परिणाम यहां भी प्राप्त होता है। तथ्य यह है कि लाइसेंस को संभवतः 1955 के आदेश के खंड 7 के तहत पुनः वैध किया गया था, उपरोक्त निष्कर्ष को और मजबूत करता है। श्री डीएन मुखर्जी का यह कहना कि यह विस्तार लाइसेंस के अंतिम पैराग्राफ के तहत था, संपूर्ण मामला नहीं है। उस अनुच्छेद द्वारा एक शक्ति आरक्षित की गई हो सकती है लेकिन यह केवल (1) [1964] 1 एससीआर 830 ही हो सकती है।

7 दिसंबर 1955 के बाद लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा 1955 के आदेश के आधार पर प्रयोग किया गया क्योंकि पिछले सभी आदेश निरस्त कर दिए गए थे। इस प्रकार 1955 के आदेश के खंड 5 के उल्लंघन के लिए आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम की धारा 5 के तहत एक अपराध था। श्री डी.एन. मुखर्जी लाइसेंस के हस्तांतरण और लाइसेंस के हस्तांतरण के बीच अंतर करना चाहते हैं। मशीनरी. यह तर्क हमें स्वीकार्य नहीं है. लाइसेंस ने अपनी शर्तें बनाईं कि माल का उपयोग लाइसेंसधारी द्वारा किया जाएगा और परिस्थितियों में माल का हस्तांतरण लाइसेंस के हस्तांतरण के समान है। लाइसेंस के हस्तांतरण और माल के हस्तांतरण के

बीच अंतर करना बहुत ही सूक्ष्मता से मामला होगा। भले ही कोई अंतर निकाला जा सके, लाइसेंस लाइसेंसधारक के वास्तविक उपयोग के लिए था। जब माल बेचा गया तो शर्त संख्या 7 टूट गई और यह 1955 के आदेश का उल्लंघन होगा जो लागू हो चुका था।

अंतिम प्रश्न यह है कि क्या कनोरिया के बारे में कहा जा सकता है कि उसने कोई अपराध किया है और क्या उस पर कोई मुकदमा चलाया गया था। 1960 में संशोधित धारा उल्लंघन के लिए उकसाने को अपराध बनाती है। यदि संशोधन लागू होता है क्योंकि अभियोजन संशोधन के बाद था (एक बिंदु जिसे हमें तय करने की आवश्यकता नहीं है) कनोरिया निश्चित रूप से कम से कम उकसाने का दोषी होगा। हमारी राय में इस बिंदु पर निर्णय करना आवश्यक नहीं है क्योंकि कनोरिया एक प्रमुख अपराधी के रूप में दोषी है और जो धारा मूल रूप से थी, वह उस पर लागू होनी चाहिए। धारा में कहा गया है,

> "यदि कोई व्यक्ति किसी दिए गए आदेश का उल्लंघन करता है या किया गया समझा जाता है..." तो उसे कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माने से, या दंडित किया जाएगा। दोनों।"

सवाल यह है कि क्या कनोरिया ऐसा व्यक्ति था। कनोरिया लाइसेंस जारी करने और लाइसेंस के अंतर्गत आने वाले माल के हस्तांतरण के लिए

जिम्मेदार था। उसने इन दोनों मामलों से जुड़े हर दस्तावेज को लिखा। इसलिए, वह जिम्मेदार था मुख्य रूप से कंपनी के साथ। वास्तव में कंपनी उल्लंघन का अपराध नहीं कर सकती थी यदि कनोरिया ने वैसा कार्य नहीं किया होता जैसा उन्होंने किया। दुष्प्रेरण, जिसके बारे में धारा अब बात करती है, एक अलग प्रकार का कार्य है। कनोरिया का कार्य नहीं था किसी और को उकसाना, लेकिन जिसने स्वयं 1955 के आदेश का उल्लंघन किया और इसलिए, वह मुख्य रूप से उत्तरदायी था। शिकायत में कोई संदेह नहीं था कि वास्तव में किसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाना था, लेकिन इसमें कनोरिया को एक आरोपी के रूप में वर्णित किया गया था. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 537 के स्पष्टीकरण के तहत शिकायत में किसी भी त्रुटि, कमीशन या अनियमितता के कारण यह निष्कर्ष उलट नहीं जाना चाहिए था कि कनोरिया दोषी था, जब तक कि ऐसा न हुआ हो। न्याय की विफलता. आपत्ति इस बात पर है कि उनका नाम नहीं लिया गया. पूरी शिकायत में एक आरोपी के रूप में और इस प्रकार वह आरोपी नहीं था, इसे मुकदमे में उठाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके विपरीत कनोरिया ने अपनी ओर से दोषी नहीं होने की याचिका दायर की और एक आरोपी के रूप में परीक्षण भी किया। यह स्पष्ट है 94 7 कि उसे अभियुक्त माना गया और वह अपनी स्थिति को समझता था। उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण में आपत्ति पर विचार नहीं किया जा सका क्योंकि

इसमें देरी हुई थी और दोष, यदि कोई हो, न्याय की विफलता का कारण नहीं बना था। इस मैदान में भी कोई ताकत नहीं है.

उपरोक्त कारणों से हम संतुष्ट हैं कि उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी की सजा में हस्तक्षेप करके गलती की। हम तदनुसार अपील की अनुमति देते हैं, उच्च न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के आदेश को रद्द करते हैं और धारा के तहत दोषसिद्धि को बहाल करते हैं। आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम की धारा 5, रुपये के जुर्माने के साथ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज की गई। 200 या एक माह का साधारण कारावास।

अपील की अनुमति

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी मदन लाल सहारन (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।